MR. SPEAKER: I have not held it in order. I am not accepting it.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I have not been told about it.

MR. SPEAKER: If I had accepted it, you would have been told

PROF. MADHU DANDAVATE: I have made a concrete submission that in view of the urgency of the other matter, my privilege motion might be taken up tomorrow and the other issue given priority In the past there have been precedents when members have requested that such motions might be taken up the next day. Since the other motion involves the question of the dignity and honour of the entire House—it is not a question of any party—I suggest it might be taken up today and mine may be taken up tomorrow.

MR SPEAKER: I can say later on, but not definitely tomorrow; it depends on the order of the business.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I have asked for suspension of the rule with regard to a privilege motion which stipulates that not more than one motion could be taken up on one day. There also I have a motion.

MR. SPEAKER: This is a pending matter. It cannot be treated as a second one.

PROF. MADHU DANDAVATE: Let it remain pending for one more day. Earlier some members had demanded that the question hour should be suspended to discuss the other privilege motion and you said it could be taken up after the question hour. I have also said that there have been precedents when privilege motions have been postponed to another day. So mine may be taken up on some other day.

MR. SPEAKER: I am not treating it is a precedent. It is just a submission. Why do you bring it like this? Tomorrow the Minister might not be available. Today I had specially directed him to come and explain it here. I cannot commit myself to tomorrow. It may be later on. Do you agree to that?

PROF. MADHU DANDAVATE: I am suggesting that it might be put up on any day that you consider convenient.

MR. SPEAKER: That is all right. We can take it up on a later day.

QUESTION OF PRIVILEGE

CERTAIN STATEMENTS MADE BY THE MINISTER OF COMMERCE IN RAJYA SABHA RE. ALLEGED SIGNATURES OF SOME M. PS. ON A REPRESENTATION FOR ISSUE OF LICENCES

MR SPEAKER: There is a privilege motion given notice of by many members, Shri Madhu Limaye, Shri Shyamnandan Mishra, Prof. Madhu Dandavate, Shri P. G. Mavalankar and Shri Jyotirmoy Bosu.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Gwalior): What about my motion?

MR. SPEAKER: I do not find it here.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: I have given notice under Rule 184. I want a Parliamentary Committee to be set up.

MR. SPEAKER: This will come later on.

श्री मधु लिमये : (बांका) : अध्यक्ष महोदय कल ही में ने इस सम्बन्ध में सदन की मान-हानि का नोटिस आप को दिया था। कल शाम को 6 बजे में खुद राज्य सभा की कार्यवाही को सुनने के लिए गया था और उस कार्यवाही को सुनने के बाद, अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगा कि कुछ नई बातें आप के सामने रखनी चाहिए। इसलिए चार सफों का नया नोटिस भी मैंने आप को दिया है। अध्यक्ष महोदय, इस में तीन तरह के मान-हानि भंग के प्रकार हो गये हैं। नं० 1 तो यह

है कि व्यापार मंत्री प्रो० चट्टोपाध्याय ने इस सदन के सदस्यों के बारे में राज्य सभा में जो वक्तव्य दिया, उस से इस सदन की मान-हानि हुई है। इसलिए पहला मेरा मान-हानि का आरोप तो प्रो० चट्टोपाध्याय के खिलाफ़ है और क्योंकि वे राज्य सभा के सदस्य हैं, इसलिए राज्य सभा के चेयरमैन से बात करके उस मामले को आगे बढ़ाना पड़ेगा।

मेरा दूसरा विशेषाधिकार का जो नोटिस है, वह भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्री और वर्तमान रेल मंत्री श्री ललित नारायण मिश्र के खिलाफ़ है और साथ ही 21 जो इस लोक सभा के सदस्य हैं, जिनके बारे में यह कहा गया है कि उन्होंने आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर किये जिस के आधार पर 7 व्यक्तियों को, जो पाँडीचेरी यूनियन टैरिटरी के विभिन्न फ़र्मों के लोग हैं, जिनको लाइसेन्स दिये गये हैं, तो इन लोगों के खिलाफ़ भी मेरा नोटिस है। लेकिन वे गलतफ़हमी में न पड़े इस बात को लेकर कि जिन के हस्ताक्षर फोर्ज किये गये हैं, उन के बारे में भी मैं औपचारिक नोटिस दे रहा हूं इस का यह मतलब नहीं कि मेरा मन उन के बारे में बना हुआ है। मैं केवल इसलिए दे रहा हूं कि उन के बारे में अभियोग लगा हुआ है कि इन्होंने हस्ताक्षर किये थे।

तो अध्यक्ष महोदय, कुछ बुनियादी बातों को आप के सामने रखना चाहता हूं। मेरी जानकारी के अनुसार इन लाइसेंसों के बारे में जो पहले आवेदन पत्र दिये गये थे, इनके पहले के जो विदेश व्यापार मंत्री या व्यापार मंत्री थे, उनके मंत्रालय के द्वारा यह अस्वीकार कर दिये गये थे यानी इन लाइसेंसों की एप्लीकेशन अस्वीकार कर दी गई थी। लेकिन बाद में इनसदस्यों के हस्ताक्षर जिस आवेदन पत्रों पर है, जो 23-11-72 को, प्राप्त हुआ यह जानकारी प्रो० चट्टोपाध्याय ने दी है, उस के आधार पर नये लोगों को लाइसेंस दिये गये हैं और आज बम्बई से मुझे समाचार मिला है कि जिन लोगों को ये लाइसेन्स दिये गये हैं, ये लोग अपने लाइसेंसों को बेच रहे हैं इन्टरमीडियेरीज के द्वारा। जो व्यापार मंत्रालय के द्वारा हैंडबुक प्रकाशित किया गया है उस के तहत, अध्यक्ष महोदय, ट्रैफिकिंग इन लाइसेंसज, यह अपराध है, जब तक कि माल मंगवाया नहीं जाता, डिलिवरी नहीं होता, तब तक वह माल बेचा नहीं जा सकता। यह आप के नियम हैं और इन नियमों का भी उल्लंघन हुआ है। जो लाइसेंस दिये गये और उन के लिये जो लेटर आफ़ आथॉरिटी होता है उस का भी उल्लंघन हुआ है। लाइसेंसिंग में ट्रैफिकिंग हो रहा है और अध्यक्ष महोदय, यह पूरा जो मामला है, यह गैर-कानूनी मामला है और बहुत ही गंदा मामला है। इसमें रिश्वत दी गई है और ली गई है। यह इस की पृष्ठभूमि है।

अध्यक्ष महोदय, जब इस के बारे में ब्लिट्ज साप्ताहिक में खबर छपी तो प्रो० चट्टोपाध्याय के कथनानुसार, इस की जांच सी० बी० आई० ने शुरू की। सी० बी० आई० वाले उन सदस्यों के पास पहुंचे जिनके नाम इस आवेदन पत्र पर थे और इनमें से कई सदस्यों ने कहा मुझे यह बताया गया और प्रो० चट्टोपाध्याय ने भी यह राज्य सभा में कहा कि हमने हस्ताक्षर नहीं किया था और ये बनावटी हैं, झूठे हैं और जेन्यून नहीं हैं लेकिन इन में से एक सदस्य ने आकर जिसका सबसे पहले नाम है, मैं उन सदस्यों की सूची पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि अखबार में वह आ चुकी है, श्री तुलमोहन राम का पहला नाम है और उन्होंने सी० बी० आई० से कहा है कि हां, मेरे हस्ताक्षर हैं। तो इस में यह सवाल उठता है कि जब प्रो० चट्टोपाध्याय को मालूम था कि कुछ सदस्यों ने कहा है कि हमारे हस्ताक्षर जेन्यून नहीं हैं, तो उन का वहां पर नाम क्यों लिया? जब उन को यह भी

[श्री मधु लिमये]

मालम था कि एक सदस्य ने कबूल किया हैं कि मेरे हस्ताक्षर हैं तो उन को यह नहीं कहना चाहिए था कि जिन तीन सदस्यों ने इंकार नही किया है, उन के बारे में भी मेरा प्रिजम्पशन है कि इन के हस्ताक्षर भी बनावटी हैं । अध्यक्ष महोदय, दोनों बातें आप देखिये कि जिन के बारे में उन को जानकारी थी कि उन के हस्ताक्षर फोर्ज किये गये हैं, मेम्बरों के कथनानुसार, उन के नाम लेना और जिन के बारे में उन्हे यह जानकारी थी कि उन के हस्ताक्षर हैं, उन के बारे में यह कहना कि मेरा प्रिजम्पशन है कि वह भी फोर्ज है, ये दोनो ही अनुचित काम प्रो० चट्टोपाध्याय ने किये हैं ।

जहा तक श्री ललित नारायण मिश्र का सवाल है, उस समय वे विदेश व्यापार मंत्री थे और उनके यहां कार्यालय में या घर में यह सारा षडयंत्र रचा गया । श्री तुलमोहन राम के हस्ताक्षर से यह तैयार किया गया और उन्ही लोगो के खिलाफ वह जानकारी मिली है कांग्रेस के सदस्यो के मार्फत कि यह भी तय हुआ कि कुछ सिगनेचर इस मे फोर्ज किये जाएं ।

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : यह गलत है ।

श्री मधु लिमये : अब मेरे पास कोई साधन नही है, कोई इवैस्टीगेटिंग एजेन्सी नही है जो मैं सही जानकारी हासिल करूं लेकिन जो मेरे पास खबरें पहुच रही है, उन को मैं आपके सामने रख रहा हू कि श्री ललित नारायण मिश्र के कार्यालय में या घर मे एक यह आवेदन पत्र तैयार किया है । उस के ऊपर आप सफ़ाई दे सकते हैं । मैं केवल यह कह रहा हूं कि आप के इंकार करने से कुछ नही होने वाला है । इस की पूरी जांच जब तक नही होती है, सत्य सामने नही आयेगा । मैं यह तो दावा नही करता कि मेरी सब बातें सौ फीसदी सही हैं और आप के इंकार से भी कोई बात नही होने वाली है । जो जानकारी मुझे मिली हैं उस को में रख रहा हूं । इसलिए श्री ललित नारायण मिश्र का सम्बन्ध इस में आता है कि यह सेवी डील उन के मंत्रालय में तब हुआ जब कि वे अधिकार में थे । दूसरी बात यह है कि इन्होंने जिन सज्जनों को 'सज्जन' कोट में कह रहा हूं अगर उन को सज्जन कहना है लाइसेन्स दिये वे लोग सारे कानूनो को तोडकर उससे पैसा बना रहे हैं । 30 लाख रुपये की रिश्वत कैश में दी गई है क्योंकि तकरीबन 30 लाख रुपये के लाइसेन्सज हैं । चार सौ से अधिक उसके पीछे प्रीमियम है । मै अतिशयोक्ति नही करना चाहता हूं । उस में शराब है ——

SHRI N. K. SANGHI (Jalore): On a point of order, Sir. The hon. member is not in possession of any papers or documents containing facts. It is based only on information gathered from hearsay. Unless he is in possession of facts, he should not be allowed to say these things.

श्री मधु लिमये : सदन की खिदमत म पेश कर रहा हू । दावा नही कर रहा हू कि सौ प्रतिशत सही है । मैं प्राइमा फेसाई केस रख रहा हू इनवेस्टीगेशन के लिए ।

मुझे एक मंत्री ने कहा—इस वक्त मुझे पता नही कि उनका नाम लेना उचित होगा या नही और मैं नाम ले भी नही रहा हूं—कि नियम!–स कार का ऐसा है कि सी बी आई के द्वारा सदस्यों की गतिविधियो के बारे में इनवेस्टीगेशन नही हो सकता है, केवल वेरिफिकेशन ही वह कर सकता है, यही पूछ सकता है कि आपके हस्ताक्षर हैं या नहीं हैं। इनवस्टीगेशन का काम सी बी आई साधारण तौर पर नहीं करता । इस वास्ते इस सदन की कोई कमेटीयां इस तरह की कोई मशीनरी होनी चाहिए जो इसकी जांच कर सके। मंत्री महोदय अपना नाम यहां पर रखने की मुझे इजाजत देंगे तो मैं बाद में बताऊंगा । लेकिन फिलहाल उनकी

इजाजत नहीं है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेता हूं ।

जिन 18 सदस्यों ने कहा कि हमारे हस्ताक्षर जाली हैं उनके बारे में मैं कोई लांछन नहीं लगाना चाहता । किन्तु एक उदाहरण श्री कानूनगो का हो चुका है जिस का जिक्र मैंने किया था । जो पत्र मैंने यहां मेज पर रखा था कुली मस्तान को पासपोर्ट देने के लिए सिफारिश-पत्र गवर्नर कानूनगो का उसके बारे में आप लोगों ने हल्ला करके कहा था कि यह जाली पत्र दे दिया है । श्री कानूनगो आप के साथी रहे हैं । तब प्रधान मंत्री सामने आई थीं और उन्होंने कहा था कि मैं इसकी जांच करूंगी । उन्होंने गवर्नर को पत्र लिखा और मुझे इत्तिला दी कि गवर्नर कहते हैं कि यह जाली पत्र है । मैंने तब कहा कि अगर जाली पत्र है तो कुली मस्तान के खिलाफ फोर्जरी का केस होना चाहिए । केस हुआ और उस केस में यह साबित हुआ कि पत्र दिया था वह बनावटी नहीं था सही पत्र था और मैं विंडीकेट हो गया (व्यवधान)

मैं खत्म कर रहा हूं अठारह सदस्यों के ऊपर संदेह का क्लाउड रह वह मैं नहीं चाहता हूं ।

जहां तक मेरा सवाल है अगर वे कहते हैं कि हमारे हस्ताक्षर नहीं है तो मैं शायद विश्वास कर लूंगा कि लेकिन इसमें साठ करोड़ भारत की जनता का सवाल है इस सदन की गरिमा का सवाल है, इसलिये उनके हित में है कि जिनके वास्तवमें मिसनेचर फोर्ज किये गये हैं कि पूरी जांच के बाद उनको फुल्ली क्लीयर किया जाय पूर्णतया उनको क्लीयर किया जाय मैं चाहता हूं कि जो जांच समिति या जांच समितियां या प्रिवलेज कमेटी बैठे वह या तो उनको पूर्णतया क्लीयर करे और अगर वह कहती है कि नहीं, हमने हैंडराईटिंग एक्सपर्ट को दूसरे लोगों को गवाहियां . . .

श्री शशि भूषण (दक्षिण दिल्ली) उन्होंने तो कहा है कि हमारे सिगनेचर नहीं है ।

श्री मधु लिमये : क्लीयरेंस में चाहता हूं और इसलिये चाहता हूं कि जो उस में अपराधी हैं । वे सार्पली फोकस में आय नहीं तो वे उनकी आड में छिपे रहेंगे शेडी डील में जो हिस्सेदार हैं या जिन्होंने रिश्वत ली है और दिलाई है, वे उनकी आड में छिपे न रह सकें इसलिये मैं चाहता हूं कि जिनके हस्ताक्षर फार्ज किये गये हैं। उनको फुल्ली क्लीयर किया जाय उनको पूरा क्लीयरेंस मिलना चाहिये । मेरा सुझाव है कि या तो सदन का विशेष कमेटी बना करके उसके सामने आप इनवेस्टीगेशन के लिये मामला दें या प्रिवलेज कमेटी के सामने दें लेकिन फिलहाल मेरा यह चाहना है कि रिपोर्ट इस सदन के सामने पहले आय और उसके बाद जो हमको कार्यवाही करनी है उसके ऊपर हम विचार करें । इस वक्त मैं नहीं चाहता हूं ! (व्यवधान)

SHRI K NARAYANA RAO (Bobbili) Sir, I rise on a point of order I have listened with patience to Shri Madhu Limaye's explanation From all these things I fail to understand where precisely is the question of privilege If we analyse it into two or three points one fact is that some people have forged the signature of some people If there is any such forgery, he can go to a court of law.

MR SPEAKER Why do you give your own pronouncement?

SHRI K NARAYANA RAO What Shri Madhu Limaye has stated cannot be a matter for a privilege issue Both the signatures are there and it is a matter for the courts of law to decide

MR SPEAKER Kindly sit down I have received a motion under rule 184, some motions under other rules, a motion of privilege and so on, So far it has not been decided what shape it will take I am just listening to the discussion. I have not decided about

[Mr. Speaker]

any motion, as to what shape it should take. I would informs Shri Madhu Limaye that if allegations against certain members are to be made, then there is a different procedure. If you want to put it in that shape, then you will have to give notice to those members. But if in a broad sense you are taking it in the shape of some broad interest, the interest of the members and so on, I have no objection.

श्री मधु लिमये : यह इनका व्यूप्वाइंट है प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है । इस में जल्दी में फैसला नहीं होना चाहिये ।

दो बातें मैं अन्त में कहना चाहता हूं । इन सदस्यों के हस्ताक्षरों के बारे में और इनके रोल के बारे में जो होनी चाहिये और साथ ही साथ पूरा लाइसेंसिंग जो प्रोसीजर है उसकी भी जांच होनी चाहिये । दो तरह के इंटरमीडियरीज का नाम मैंने दिया है आप को । एक नाम है इंडो बंगला देश ट्रेडिंग कारपोरेशन और उस में सदीकि जैसे कांटैक्ट मैन का भी नाम आता है ये लोग लाईसेंस बेचने में इंटरमिडियरी का काम कर रहे हैं । पूरे लाइसेंसिंग प्रोसीजर की इस उदाहरण के संदर्भ में मैं चाहता हूं कि जांच हो ।

राज्य सभा और लोक सभा के पारस्परिक संबंधों का भी यह मामला है । 21 सदस्य इस सदन के हैं और प्रो० चट्टोपाध्याय मेरा ख्याल है कि राज्य सभा के सदस्य हैं । यह मोशन प्रो० चट्टोपाध्याय के खिलाफ जहां तक होगा वह राज्य सभा के पास जाना चाहिये जहां तक हमारे सदस्यों का सवाल है राज्य सभा को कोई अधिकार नहीं है कि वह इस में जांच करें । यह काम हम लोगों को ही करना चाहिये । राज्य सभा और लोक सभा के अधिकारों और संबंधों का भी यह सवाल है । इसी एक उदाहरण में सबक सीखा जाना चाहिये और पूरे लाइसेंसिंग प्रोसीजर को देखा जाना चाहिये । सदस्यों के द्वारा इस तरह दबाव डालना, एप्लीकेशन करना यह क्या उचित है ? सरकार उससे प्रभावित हो कर कोई इल्लीगल काम करती है तो मैं समझता हूं कि यह अनुचित है जिस काले धन की और भ्रष्टाचार की हम लोग चर्चा करते हैं । उस में यह सन्निहित है ।

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai): Sir, there are, in fact, two issues involved in this matter. But both converge on the issue of privilege. There is one issue of misconduct of the hon. Members which is implied....

SHRI K. NARAYANA RAO: Let him explain how it is a misconduct. It is not a misconduct. He should not use that word.

MR SPEAKER It will be better you change it to "conduct" of the Member.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: I am explaining the issues The misconduct of the hon. Members also constitutes a breach of privilege

MR SPEAKER If you use that word, it comes to the same thing

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: Why do you interrupt me again?

MR SPEAKER. He is objecting to it. So. I am suggesting you could change it.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: I have not yet begun my sumbission on it I am explaining the issues

MR SPEAKER: What should I tell him?

SHRI PILOO MODY (Godhra): You tell him to sit down.

MR SPEAKER: That is a very good solution.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: It is a clear case of privilege. The first one also could be a breach of privilege because the hon. Member is deemed to have acted in a manner which is inconsistent with the dignity of the House, because he has enjoyed the privilege which the House confers on him for promotion of his personal interest. In both the cases, it becomes a matter of privilege.

What is the the issue that we are discussing today? Are we discussing the issue that the hon. Minister of Commerce disclosed the names of the hon. Members in the other House? That is not the issue. Any Minister can disclose the names of the Members who have acted in a particular manner. The issue is that the hon. Minister disclosed the names when the matter was under investigation and when it was in his knowledge that many of these hon. Members have denied that they have signed any paper of the kind. I cannot agree to the proposition that no Minister can disclose the names of the hon. Members of this House in the other House. That depends upon the context and that also depends upon the circumstances in which he discloses the names.

Now, here, it has been established that these hon. Members had, in fact, told the investigating authorities, quite a few months back, three or four months back, that they had not signed any paper of the kind That was in the knowledge of the hon. Minister who disclosed the names on the floor of the other Houses Therefore, a question of breach of privilege arises because here is a question of deliberate intent because he knew about it, that the hon. Members had denied about their association with such a paper. So, there was a deliberate intent established on the part of the hon. Minister in defaming those hon. Members. That could be the presumption in this case.

Another thing is that the hon. Minister has not yet cleared decisively these hon. members from this unsavoury thing. What he has said on the floor of the House towards the evening is that these members have denied. The Minister has not made any clear and decisive statement that these signatures happen to be forged ones. He has not. So, the members remain under cloud because of the act of disclosure by the hon. Minister in this case He need not have disclosed the names; he could have taken the plea of public interest because the matter is under investigation and that is a fact subject for a plea under public interest. But the Minister did not think it fit to take the plea of public interest and he has disclosed the names. Ultimately also, towards the end of the day, he did not clear these hon. members decisively, categorically and finally So, these members remain under cloud. The hon. Minister still seems to suggest that the matter requires further investigation and determination. Therefore, if 18 out of those 21 hon. members—I do not know whether all those hon. members happen to be present in the House at this moment—had thought that the hon. Minister had cleared them, I would point out that that has not happened. So, what is the duty of the House in this matter at this particular stage? My submission is that this matter. .

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF ELECTRONICS AND MINISTER OF SPACE (SHRIMATI INDIRA GANDHI): I am listening with great attention to the hon. Member. Obviously he has not read the question which was asked of the hon. Minister or the answer which he gave originally, apart from the explanation afterwards.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: I have not understood the Prime Minister's observations. I am sorry. Would you kindly repeat your observations?

SHRIMATI INDIRA GANDHI: I have said once. I do not want to repeat.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: I have read all the papers connected with this. The hon. Minister said in that House that the matter was under investigation....

श्री मधु लिमये : मैं पढ़ देता हूं। "ब्लिट्ज" में प्रकाशित समाचार के बारे मे सरकार को पता चला तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो के जरिये गुप्त रुप से जांच कराई गई। जिन संसद् सदस्यों के बारे में यह बताया जाता है कि उन्होंने ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं उन के नाम इस प्रकार है। ज्ञापन वाणिज्य मंत्रालय में 23 नवम्बर, 1972 को प्राप्त हुआ ... (व्यवधान)

MR. SPEAKER: You must take my permission.

श्री मधु लिमये : उन्होंने कहा कि आपने पढ़ा नही, इसलिए मैं उसे पढ़ कर सुना रहा हू। आप पढ़ने दीजिए। इन के लिए कहा गया कि इन्होंने पढ़ा नहीं. (व्यवधान)...

MR. SPEAKER: He can answer. Why should you bother yourself?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI A. C. GEORGE): If the hon. Member is kind enough to go through the body of the question and the body of the answer given in the Rajya Sabha, a lot of further clarifications on this could be avoided....

SHRI PILOO MODY: We want to go through Mr. L. N. Mishra's body.

SHRI A. C. GEORGE: If he reads the question and the answer, a lot of misunderstanding could be avoided. I have a doubt that the hon. Member, Shri Shyamnandan Mishra. has not read the question and the answer.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: I have not read it ?

MR. SPEAKER: After they finish, I will give a chance to your side also.

SHRI A. C. GEORGE: We agree with you, but since he is digressing away from the main body of the question, may I read it with your premission?

MR. SPEAKER: Yes.

SHRI A. C. GEORGE: Let the House know what was the question and what was the answer.

Question No. 730.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Can a Minister be allowed to get up any time he likes and make a submission?

MR. SPEAKER: If Shri Madhu Limaye can get up at any time, why not the other side?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जब सवाल आया कि इन्होंने उसे पढ़ा नहीं तब उन्होंने उठ कर उसे पढ़ा।

अध्यक्ष महोदय : तो इसी तरह वह भी खड़े हो गए, सुन लीजिए उन को भी क्या कहते हैं।

श्री अटलबिहारी वाजपेयी : वह जवाब हमारे पास भी है, इसलिए हम खड़े हुए।... (व्यवधान)..

MR SPEAKER: There is no harm if he reads it

SHRI A. C. GEORGE: The question is:

"The names of the M. Ps. who have allegedly signed the representation referred to in the Blitz Weekly of March 30, 1974 and the date on which it was received in his Ministry."

ANSWER: "(a) to (c). A statement is laid on the Table of the House."

The statement says:

"When the news item published in the Blitz came to the Government's notice, secret verification through CBI was initiated. The names of the M.Ps. who are purported to have signed the memorandum are ...."

There are 21 names.

श्री मधु लिमये : आप ने कहा एनी टाइम मैं खड़ा होता हूं। यही पढ़ने के लिए मैं खड़ा हुआ था। जो मैंने पढ़ा, वही उन्होंने पढ़ा है। मैंने हिन्दी में पढ़ा उन्होंने अंग्रेजी में पढ़ा। मेरे और उन के पढ़ने में क्या फर्क है ?

SHRI PILOO MODY: You can ask the Minister what does 'purported' mean?

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: After the hon. Minister has read out the question and the answer, I am confirmed in my observation that the hon. Minister has disclosed at a stage when he was not sure if these hon. Members are really involved in this affair because he has actually used the word which the Minister used, that is, 'purported'. Now, if that was so and if it was within his full knowledge that the matter was under investigation, the hon. Minister should have taken the plea of public interest and not disclosed the names and thereby, by this act he has brought these hon. Members into disrepute as also the House.

The second point I want to make is that the hon. Minister of Foreign Trade at that time....his subsequent disclosure has also established—has also brought the House and the members into ridicule and contempt. How? The hon. Minister by granting licence on the representation of 21 Members.. (*Interruptions*). I am bringing the issue of privilege against the then Minister. The implication is that the hon. Minister granted the licence on the representation of these 21 Members....

SOME HON. MEMBERS: No, no.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: Licence to whom? It was given to a party who had been black listed; the party was not entitled to it and, thereby, they have brought the House and the Members of the House into contempt. (*Interruptions*).

SHRI A. C. GEORGE: This is false. You are going absolutely on wrong assumptions (*Interruptions*).

श्री मधु लिमये : आपको मौका मिलेगा, आप क्यों घबरा रहे हैं—

They are trafficing in licences. (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: What is going on?

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: Now, the letter signed by these twenty-one Members is supposed to be material to the grant of licence and lends one more support to the implication that it is because of pressures of the hon. Members that a licence was given.

I would go by what the hon. Members on the other side say that they are not associated with it. I shall go by the version of the hon. Members. If that is so, the House has a duty to find out how this conspiracy was hatched to defame the Members; how was this forgery brought about. Therefore, an enquiry is needed. Whether that enquiry is to be conducted by the C.B.I. or not, that is the question. In a matter of this kind, as the House itself has established a convention in the past, that enquiry should be conducted by a Committee of this House because it relates to the misconduct of Members. I do not say that the Members are guilty of misconduct. It would be proper for the House to find out the basic reasons as to how the forgery was brought about; who brought about that forgery—was it brought about by the Ministry or was it brought about by the Minister himself or whether it was brought about by anyone of the 21 Members. And who conspired to bring about the forgery out of these Members?

That is a very important point which has to be established. We can

[Shri Shyamnandan Mishra]

come to some conclusions in this matter only when the issue is, in the first instance, referred to the Committee of Privileges and, in the second instance, a Committee of the House is appointed to probe into the conspiracy that had been hatched to defame 21 Members of this House.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): Sir, before we proceed, I would like to draw your kind attention to a vital document—1952—Bulletin Part II of 17th May, 1952. It reads:

> "A Member should not try to secure business from Government for a firm, a company or relation with which....."
>
> "A Member should not endorse incorrect certificate etc., etc."
>
> "A Member should not write recommendatory letter or speak to a Government official for employment of business contacts or any relation."

There are clearer rules as to what a Member should or should not do Now, Sir, on 30th March. . .

MR. SPEARER: The other day when I was quoting, it was not accepted. He says that there are clearer rules.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: You were quoting from a Hand Book The Blitz, in its issue, dated 30th March, 1974 makes a clear and categorical allegation which has not been contradicted so far. Nor has anybody chosen to proceed against the paper in a court of law. What does it say? It says:

> "Congress M.Ps. in a shoddy probe forgery drama. Recently, the Commerce Minister received letters signed by two dozen Congress Members pleading for a licence for a particular party, etc., etc.."

There is one thing final. The officer called on the Congress M. P. who headed the list and after some polite interrogations, the whole thing broke down. He admitted that he had taken from the party for whom the licence was recommended Rs. 1.50 lakhs. Has anybody proceeded against this paper? Has this news-item been contradicted?

Yesterday, they read out the names. I have a feeling, some people have tried to kill two birds with one stone—one is to feather his own nest and secondly he has tried to damage his party opposition. In certain factions they are fighting with each other. The other day we had a case when a visitor was introduced to the gallery by a Member on the recommendation of somebody who did not know about it.

Sir, the most significant remark of Mr. Chattopadhyaya yesterday was, 'I made it clear there was some defect in the original notification and the defect was rectified As a result of that some people debarred originally were given licences according to rules" No, these seven parties in Pondicherry were given licence, with a total value of Rs 30 lakhs and it is alleged that rupees one and a half lakhs have been given to some blooming person somewhere

The question that comes to my mind is to do these modifications in the rules which debarred these seven parties from getting licences somebody wanted a lever in hand So, he has engineered a memorandum signed by some MPs. Therefore, the foreman was chosen and he was asked to organise this massive forgery and the rules were amended which debarred these parties from going for licences

Sir, another important thing is the hon. Commerce Minister—although the CBI had revealed the name of the Member—has not revealed whether any action has been taken. He has instead chosen to beat about the bush. One hon. Member in the other House said, the corridors of Foreign Trade Ministry have become darker. How right he is! Why did the present Minister choose to conceal the fact that one Member has already

made a confession before governmental agency. That part he has chosen to keep out. So, many people are hand in glove with whole affair. In May's *Parliamentary practice* it is clearly said:

> "If any complaint is against any individual Member or against any officer of the other House the usual mode of proceeding is to examine into the fact and then lay the statement of that evidence before the House of which the person complained of is Member"

So, this is a flagrant violation of the said procedure. The Commerce Minister has chosen to go in hiding the news violating the norms of procedure.

So, I will say there is a breach of privilege and the Member concerned, Mr. Tulmohan Ram till he gets absolved from that charge, has committed an act which has brought down the House in the eyes of the people. So, he has committed a breach of privilege.

13.00 hrs

Secondly, the Commerce Minister, instead of giving full facts about the confessional part of it, has chosen to withhold information, and thus he has committed another breach of privilege.

Thirdly, to get all the information, two things are immediately necessary, firstly that all the files connected with this matter should be seized by you, Mr. Speaker, and the files should be sealed at once, so that the files are not tampered with, because my information is that people have been working very briskly last night in the Foreign Trade or Commerce Ministry and they have been altering the pages of the file, and secondly that we require a parliamentary committee, an all-party parliamentary committee chosen from both Houses, to sit in judgment, make a thorough probe and fix responsibility as to how much money was squeezed out of these licences, how much has gone to party funds, how much has gone to individuals, and Mr Tulmohan Ram, if he has committed this— this is what we are alleging— should be removed from this House.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, इस गम्भीर मामले के सम्बन्ध में कुछ तथ्य सदन को स्मरण रखने होंगे । पहली बात यह है कि वाणिज्य मंत्रालय में 23 नवम्बर, 1973 को ज्ञापन प्राप्त हुआ, बम्बई के साप्ताहिक में समाचार बाद में छपा है और जैसा वाणिज्य मंत्री ने कहा उस ज्ञापन के साथ 21 लोक सभा के सदस्यों के हस्ताक्षर थे । सवाल यह है कि जिस ज्ञापन पर लोक सभा के सदस्यों के हस्ताक्षर थे और जो 1972 में प्राप्त हुआ उसकी जांच में इतना विलम्ब क्यों किया गया ? यह भी देखना होगा कि उस समय वाणिज्य मंत्री कौन थे, यह ज्ञापन किसको मिला, क्या यह ज्ञापन डाक से आया या यह ज्ञापन मन्त्री महोदय के हाथ में दिया गया और यह ज्ञापन किसने लिया—यह प्रश्न अभी तक अनुत्तरित है । लेकिन जब वर्तमान वाणिज्य मंत्री के सामने मामला आया ——

श्री शिवाजीराव एस० देशमुख (परभणि) ज्ञापन कब दिया और लाइसेन्स कब मिला यह भी सवाल है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वर्तमान वाणिज्य मन्त्री के सामने एक रास्ता खुला हुआ था, जिन 21 लोक सभा सदस्यों के नाम हैं ज्ञापन में उससे वे सम्पर्क करके पता लगा सकते थे कि सचमुच में इस आशय का कोई पत्र लिखा है या नहीं लेकिन वे अपने कर्त्तव्य पालन में विफल रहे । मामला सी

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

बी आई को सौंप दिया गया ऐसा मामला जिससे पार्लियामेन्ट के मेम्बर जुड़े हुए हैं ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : इसमें सी० बी० आई० ने खुद इंक्वायरी शुरू की है क्या ? यह मैं इसलिए निवेदन करता हूं चूंकि सी० बी० आई० ने हम लोगों से बताया इसमें एक डिस्क्रिमिनेशन आता है, सबसे उन्होने बताया कि हम मिनिस्टर के खिलाफ कोई भी इंक्वायरी नहीं करेंगे स्वयं । अगर उन्होंने मेम्बरों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की है तो यह हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन है । हम लोगों से कमेटी में सी० बी० आई० वालों ने बताया कि हम मिनिस्टर के खिलाफ स्वयं इंक्वायरी नहीं कर सकते और न करते हैं और अगर मेम्बरों के खिलाफ उन्होंने इंक्वारी की है तो यह हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : किसी भी मामले से अगर पार्लियामेन्ट के मेम्बर्स सम्बन्धित हैं, उनके आचरण से जुड़ा हुआ प्रश्न हैं तो सरकारी एजेंन्सी उसकी जांच करे—मैं इसके हक में नहीं हूं । पार्लियामेन्टरी कमेटी के समाने वह मामला जाना चाहिए । कल भी वाणिज्य मंत्री ने जो कुछ कहा उससे 18 सदस्य भी सन्देह से मुक्त नहीं हैं । वैसे तो दो तीन मेम्बरों की तरफ से मौन धारण किया हुआ है । (व्यवधान) अभी तक—

श्रीमती सावित्री श्याम (आंवला) : उन नौ सदस्यों में एक मैं भी हूं । मैंने स्पीकर साहब को अपना डिनायल लिखकर भेज दिया है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : देवीजी, आप इसमें कहां फंस गईं ? (व्यवधान)

श्री मधु लिमये : अगर श्री तुलमोहन राम इनकार भी करेंगे तो कौन मानेगा। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बम्बई के साप्ताहिक ने एक गम्भीर आरोप लगाया है कि 21 मेम्बरों की सूची में जिनका पहला नाम है उन पर यह आरोप है कि उन्होंने लाइसेंस दिलाने के लिए रिश्वत ली । अब वह सेक्स्य कौन हैं, यह सभी जानते हैं । कल वाणिज्य मंत्री ने उनको मुक्त नहीं किया है । उन्होंने जिन 18 सदस्यों के नाम पढ़े हैं राज्य सभा में—और यह भी बड़ी विचित्र बात है कि 18 सदस्यों उनको सम्पर्क करते उसके बजाये वाणिज्य मंत्री ने उन को सम्पर्क किया । खैर, सम्पर्क किया अच्छा किया लेकिन यह भी खबर आई है कि वाणिज्य मंत्री को धमकी दी गई है कि अगर हमारा नाम क्लियर नहीं किया तो हम तुम्हारे इस्तीफे की मांग करेंगे । प्रधान मन्त्री ने भी वाणिज्य मंत्री की खबर ली है ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जी नही, मैंने किसी की खबर नही ली है, इस सिलसिले में ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : प्रधान मन्त्री कह रही है उन्होंने किसी की खबर नही ली है ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इस सिलसिले में ।

अटल बिहारी वाजपेयी : क्या यह सच नहीं है कि श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय को आपने अपने कक्ष में बुलाकर डांटा ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : जी नहीं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह 'जी नहीं" बड़े जोर से कहा गया है, मेरी इच्छा है मैं इसको मान लूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप मान ही लीजिए और आगे बढ़िये ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अच्छा होता अगर प्रधान मन्त्री की ओर से स्वयं खण्डन आता । समाचार-पत्रों में यह छपा है । (व्यवधान)

श्री श्यामनन्दन मिश्र : पार्लियामेन्टरी अफेयर्स मिनिस्टर के कमरे में मीटिंग हुई उसका भी जिक्र करिये । (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अब मैं असली मुद्दे पर आता हूं ।

तीन सदस्यों के बारे में अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है । यह भी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि जो सदस्य यह दावा कर रहे हैं कि उनके दस्तखत जाली बनाये गए तो इस बात की जांच करनी पड़ेगी कि जाली दस्तखत किसने बनाये ? संसत्सदस्यों के साथ इतनी बड़ी जालसाजी करने वाला कौन है ? और यह क्या वजह है कि सभी कांग्रेस पार्टी के सदस्य ही जालसाजी के शिकार हुए । हम में से कोई शिकार नहीं हुआ ? (व्यवधान) हम तो होने ही नहीं शिकार। तो यह जांच करनी पड़ेगी कि जालसाज कौन है, जालसाजी किसने की ? इसके बारे में भी जांच करनी पड़ेगी क्या मंत्रालय का तरीका यह है कि अगर लाइसेन्स के बारे में पार्लमेन्ट के मेम्बर लिख दें तो बिना मेरिट में जाये हुए कि उन कम्पनी को लाइसेंस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, उसको लाइसेन्स दे दिया जायेगा ? अगर ऐसा हो तो जरा हमको भी बता दीजिए । क्या विशेषाधिकार केवल सत्ताधारी पार्टी के सदस्यों को ही प्राप्त हैं ?

मेरा निवेदन है कि लोक सभा के सदस्यों के आचरण से संबंधित यह मामला है, सारी लोक सभा की प्रतिष्ठा आज दांव पर लगी हुई है । आज एक पढ़े-लिखे व्यक्ति के मुंह पर चर्चा है कि पार्लमेन्ट के मेम्बर गलत तरीके से लाइसेन्स दिलाते हैं । इसलिए आवश्यक है कि इस मामले की जांच की जाये लेकिन क्षमा कीजिए सी० बी० आई० की जांच न तो पर्याप्त है और न उस पर हमको विश्वास है । मैंने इस सम्बन्ध में एक मोशन दिया हुआ है :

"That with a view to ensure high standards of conduct in public life and particularly by Members of Parliament, a Parliamentary Committee presided over by the Speaker and comprising of 10 members nominated by him be constituted to examine the entire episode relating to the representation made to the Ministry of Commerce over the alleged signatures of 21 Members of Lok Sabha, the revelation made by the Minister that most of these signatures are forged and the actual allotment of licences to parties mentioned in the representation and to make necessary recommendations in this regard".

मैं चाहूंगा सत्तारूढ दल भी मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करे ताकि यह मामला जल्दी से जल्दी जांच के बाद सदन के सामने आये । जो निरपराध हैं उन पर किसी तरह का लांछन नहीं लगना चाहिए लेकिन जो अपराधी हैं उन्हें कठघरे में खड़ा करके कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए ।

SHRI S M. BANERJEE (Kanpur): Sir, nobody has spoken from my party.

MR SPEAKER: It is not a question of debate. These are the motions given and to those Members who have given the motions, I am giving a few minutes.

SHRI S M. BANERJEE: Sir, kindly allow me five minutes.

MR SPEAKER: No, please.

MR. DANDAVATE, your motion is on the same matter.

Mr. Madhu Limaye has already spoken on behalf of your party.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): I have nothing to add to what my colleague Mr. Madhu Limaye has said.

MR. SPEAKER: Mr. Mavalankar.

SHRI HARI KISHORE SINGH (Pupri): Sir, we should be given an

[Shri Hari Kishore Singh]

opportunity. Our names are involved. We have written to you.

MR. SPEAKER: I will permit a few Members. I will permit the Minister also.

SHRI P. G. MAVALANKAR (Ahmedabad): Mr. Speaker, Sir, I must say, I look at this problem from a slightly different angle. Sir, in the speeches that have been made so far, it has been made clear that the whole matter relates to the dignity of the entire House, and political considerations and political controversies need not be projected into the whole affair. But, I am sorry to find, both from the tone of speeches made on this side as well as from the interruptions from the other side, that although it is said to be a matter pertaining to the entire House, certain political and controversial tinge is being given to it. I do not want to do that. Therefore, Sir, I think we ought to look at this problem from two specific angles. One is, Sir, the question of privilege The other is, the question of all that has happened with regard to the licensing procedures and practices that obtain in the Ministry of Foreign Trade or now the Ministry of Commerce. I am not here raising this issue under that guise, trying to pass any *mala fide* comment or allegations against this or that Member because I am not in possession of the facts. This is left to the CBI and other appropriate authorities to go into all these questions. But, Sir, what really disturbs me is that the conduct and honour of not one, but several Members of this House, and therefore, of this entire House, is involved. This is not a matter to be dealt with merely by a CBI enquiry. My point is, the entire episode needs a thorough probe under your direct guidance, under your direct control and Chairmanship, by an all-party Parliamentary Committee, all parties including some people who do not belong to any party. Let the Speaker choose from among those who are unbiased. Sir, I would put it this way. Sir, it is below the dignity of any hon. Member of this House that he is subjected to a scrutiny by a Government authority. If something wrong has been done by us separately, individually or collectively or in a group, let this House itself constitute a small Committee under your Chairmanship or under your guidance and let that Committee inquire fully and decide. I ask for a Parliamentary Committee to go into the whole matter, probe into it thoroughly, objectively, impartially and fully, and then come to a decision. This is one important point.

Secondly, my point of privilege comes here. I agree that whatever happens in the other House is a matter for that House. May's *Parliamentary Practice* is clear on this. I am referring to the practice that obtains in the House of Commons as well as in the House of Lords. Both the Houses are totally independent one of the other and one cannot go into the other's proceedings. According to May there subsists a perfect equality between the two Houses.

If an allegation is made against a member of one House in the other House, instead of bringing it up in that House, the matter should have been referred by the Presiding Officer of that House to the Presiding Officer of the other House, to which the member belongs. Moreover, it is no use the Deputy Minister of Commerce quoting his senior minister as having said, "purported to have". Even then, the Commerce Minister should have withheld that information from the other House and passed it on to the Speaker of this House through the Chairman of the other House. Therefore, a privilege is involved, because only this House can go into the conduct of members of this House, and none else, including the other House, can do it. So, this matter should be referred to the Privileges Commitee.

I agree with Mr. Vajpayee that it is unfortunate that all the 21 members belong to the same party, i.e. the Ruling Congress. But it is fortunate in this sense that since they all be-

long to the same party to which the minister also belongs, he could have consulted them first before he came out with this information publicly in the other House. He has not only insulted his own party people, but he has insulted this whole House. It does not matter that he has now gone to Teheran; ultimately this Government is jointly responsible to this House. So, it needs to be looked into from two aspects—a thorough probe by a committee nominated by the Speaker and functioning directly under the Speaker, and secondly, a reference to the Privileges Committee as to how far the Commerce Minister, who is not a member of this House, was within his rights to raise in the other House a matter pertaining to the conduct and dignity of members of this House without referring it to the Speaker of this House through the Chairman of the other House. I feel the matter is very serious and grave. There ought to be some areas in our public life, in parliamentary democracy, which must be above suspicion. Members of Parliament and members of the judiciary must be independent and upright and beyond the doubt of anybody indeed their behaviour must be such as Caesar's wife is above suspicion. But, here on a mere suspicion, and with an unfortunate charge of forgery, the Commerce Minister chooses to list 21 members of this House, a substantial majority of whom are saying that they are innocent and thus discredit the whole House and bring down in the esteem of the public of this country the honour, dignity and the fair name of this House. It is a grave offence he has committed and this must also be referred to the Privileges Committee.

MR. SPEAKER: I have received notice from about 15 members that they want to offer their personal explanation under rule 357. Presumably all of them want to contradict the genuineness of their signatures. They are Shri Jagannath Mishra, Shri R. P. Yadav, Shri Md. Jamilurrahman, Dr. Sankata Prasad, Shri Mohammad Yusuf, Shri Shambu Nath, Shri Bhola Raut, Shri Ram Swarup, Shri M. P. Yadav, Shri K. C. Pandey, Shri Mohammad Tahir, Shri Hari Kishore Singh, Shrimati Savitri Shyam, Kumari Kamala Kumari, Shri Uikey and Shri Inder J. Malhotra. Because their names are involved, I will allow them an opportunity to offer their personal explanation.

SHRI PILOO MODY: Forgerers now become perjurers.

श्री सत्य चरण वेसरा (दुमका) : मेरा नाम भी इस में नहीं है। मैं भी एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आप को स्टेटमेंट देना है, तो आप भी दे दीजिए ।

SHRI H. N. MUKERJEE (Calcutta—North-East): It is exactly on giving them an opportunity that I wish to make a submission. There are so many hon. Members involved in this. Are we, here and now, sitting in judgment? I presume not.

MR. SPEAKER: Since their names have been mentioned, I have to allow them an opportunity.

श्री जगन्नाथ मिश्र (मधुबनी) अध्यक्ष महोदय, तारांकित प्रश्न संख्या 730 दिनांक 27-8-74 के उत्तर के क्रम में वाणिज्य मंत्री डी० पी० चट्टोपाध्याय ने कल अन्य संसद सदस्यों के साथ मेरे नाम का भी जो उल्लेख राज्य सभा में किया उस प्रसंग में मेरा निवेदन है कि किसी फर्म के लिये लाइसेंस के लिये उसके आवेदन पत्र पर तो न मैंने हस्ताक्षर किया और न उससे मेरा किसी तरह का ताल्लुक है।

कुछ माह पूर्व जब मेरे निवास स्थान पर सी० बी० आई के अफसर इस प्रसंग में जांच पड़ताल करने आये तो मैं आश्चर्य चकित हो गया और उनसे मैंने स्पष्टत: कहा कि इस

[श्री जगन्नाथ मिश्र]

पर मैंने हस्ताक्षर नही किया है और मेरा हस्ताक्षर जाला है। मुझे इससे किसी तरह का सम्पर्क नही है।

इस स्थिति में राज्य सभा मे मेरे नाम की चर्चा कर मैं समझता हुं कि मेरे प्रति न्याय नहीं किया गया है। अत: आग्रह है कि मेरे इस व्यक्तिगत स्पष्टीकरण को स्वीकार कर मेरे प्रति न्याय करने की कृपा की जाय ताकि मेरी प्रतिष्ठा की रक्षा हो सके।

SHRI R. P. YADAV (Madhepura): Mr. Speaker, Sir, I beg to say that I am pained to note that in reply to Starred Question No. 730 dated 27th August 1974 in the Rajya Sabha, the Commerce Minister, Mr. D. P. Chattopadhyaya mentioned my name to be one of the alleged signatories to an alleged memorandum on the basis of which some licence had been issued.

In this connection, I may tell that one C.B.I. Officer had visited my house several months back and asked me showing a memorandum that whether that signature was mine. I denied it emphatically and said that it is forged one.

It is very unfortunate that in spite of this clear knowledge, the hon. Minister of Commerce had mentioned my name.

I want to make it crystal clear that I have got no concern with any of such memorandum and my alleged signature is forged. My name has unnecessarily been dragged.

Sir, you are the custodian of the prestige of the members of this House and hence I will pray that my name should be dropped for ever and after due inquiry the culprit who forged the signature should be taken to task.

SHRI PILOO MODY: It appears that the same lawyer has drafted all the replies.

SHRI C. M. STEPHEN (Muvattupuzha): We object to the observation made .... (*Interruptions*).

MR. SPEAKER: It is very wrong on his part and it is an uncalled for observation.

SHRI MD. JAMILURRAHMAN (Kishanganj): Mr. Speaker, Sir, I beg to submit that I was much shocked on 27th August 1974 to hear that my name has been dragged unnecessarily while replying to the Starred Question No. 730 dated 27th August 1974 in the Rajya Sabha and I would like to submit the following points by way of personal explanation:—

(a) That I have not signed the alleged application for licence.

(b) That my signature is forged one.

(c) That I have no concern with the application for licence.

(d) That I emphatically denied before the C.B.I. Officer who came to me some months back to my flat for enquiry and verification of my signature and I asserted that my signature is forged one.

(e) That I have been defamed and injured by the hon. Minister for Commerce as he unnecessarily dragged my name in the Rajya Sabha though, as a matter of fact, I had already stated that my signature is forged one and I have been defamed and this House has also been defamed.

(f) That you are my custodian and guardian of the honour and prestige and of this House also and as a guardian I seek your protection.

For Mr. Piloo Mody's information, I may say that I am also an advocate and a practising lawyer. I can very well draft such things. For Mr. Piloo Mody's information, I may tell him that Mr. R. P. Yadav is also an advocate. I know him personally. I may also tell Mr. Piloo Mody that I am a practising lawyer in courts for the last 15 years.

SHRI PILOO MODY: It is possible he drafted for all of them. I do not know.

DR. SANKATA PRASAD (Misrikh): I beg to submit that I was very much shocked on 27 August

1974 to hear that my name had been dragged unnecessarily while replying to the Unstarred Question No. 730 dated 27th August, 1974 in the Rajya Sabha and I would like to submit the following points by way of personal explanation:—

(a) That I have not signed the alleged application for licence.

(b) That my signature is a forged one.

(c) That I have no concern with the application for licence.

(d) That I emphatically denied before the C B I officer who came some months back to my flat for enquiry and verification of my signature and I asserted that my signature was a forged one.

(e) That I have been defamed and injured by the hon. Minister for Commerce as he unnecessarily dragged my name in the Rajya Sabha though as a matter of fact I had already stated that my signature was a forged one, and by giving out my name in the other House I have been defamed and this House has also been defamed

(f) That you are my guardian and custodian of the honour and prestige and of this House also, and as a guardian I seek your protection, Sir.

श्री मोहम्मद यूसुफ (सिवान) : 27 अगस्त, 1974 को स्टार्ड क्वेश्चन नम्बर 730 के सिलसिले में राज्य सभा में जब मेरा नाम उसमें घसीटा गया तो इसको जान कर मुझे सख्त धक्का पहुंचा और जाती एक्सप्लेनेशन के तौर पर मैं कुछ बातें आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं :

जो दरख्वास्त लाइसेंस के लिये दी गई थी उस पर मैंने दस्तखत नहीं किये थे। जैसा कि अलेज किया गया है कि मैंने दस्तखत किये थे। मेरे दस्तखत जाली थे। लाइसेंस की दरख्वास्त के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। सी बी आई के जो अफसर कुछ महीने पहले मेरे फ्लैट पर जांच करने आये थे उनके सामने भी मैंने इससे बिल्कुल इंकार किया था और कहा था कि मेरे दस्तखत जाली हैं। कामर्स मिनिस्टर ने बिना वजह मेरा नाम राज्य सभा में इसके अन्दर घसीटा है उससे मेरी बेइज्जती हुई है और उससे मुझे दुख हुआ है चूंकि मैं पहले ही कह चुका था कि मेरे दस्तखत जाली हैं। इस तरह से इस हाउस की भी इसमें बेइज्जती हुई है। इस हाउस की इज्जत के आप गार्डियन और कस्टोडियन हैं और मैं आपकी प्रोटेक्शन की दरख्वास्त करता हूं।

श्री शम्भूनाथ (सैदपुर) कल दिनांक 27–8–74 को जब मैं संसद में आयी तो ज्ञात हुआ कि राज्य सभा में वाणिज्य मंत्री श्री डी० पी चट्टोपाध्याय ने कुछ फर्मों को लाइसेंस देने की बाबत तारांकित प्रश्न नम्बर 730 के संदर्भ में उत्तर दिया है और कहा है कि आवेदन पत्र में मेरा कथित हस्ताक्षर है और इसकी जांच पड़ताल हो रही है। मुझे इस पर अत्यन्त दुख है और मैं निम्न व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

(1) कथित आवेदन पत्र पर मेरा हस्ताक्षर कदापि नहीं है।

(2) मेरा हस्ताक्षर जाली है।

(3) मुझे इस आवेदन पत्र से कोई ताल्लुक नहीं है।

(4) कुछ माह पूर्व सी बी आई के एक अधिकारी मेरे फ्लैट पर आये थे और मुझे हस्ताक्षर दिखाया था। उस समय ही मैंने हस्ताक्षर से इन्कार किया था और कहा था कि मेरा हस्ताक्षर जाली बनाया गया है।

[श्री शम्भूनाथ]

(5) मंत्री महोदय के बयान से मेरी प्रतिष्ठा पर घोर आघात पहुचा है ।

(6) इसका निराकरण तथा मुझे सतोष तभी होगा जब इसकी पूरी जाच हो और दोषी को दंडित किया जाय ।

श्री भोला राउत (बगहा): दिनांक 27-8-74 को राज्य सभा मे प्रश्न सख्या तारांकित 730 के उत्तर मे विभिन्न ससद सदस्यो के नामोल्लेख पांडिचेरी के एलान एण्ड केमिकल के लाइसेंस की स्वीकृति के लिये संस्तुति करने वाले ससद सदस्यों के रूप मे किया गया है और उसमे मेरे नाम का भी उल्लेख है । इस सबध मे मेरा निवेदन है कि ऐसे किसी सस्तुति पत्र पर जो उक्त सस्थान से संबंधित है, मैंने कोई हस्ताक्षर नही किया है । और न अन्य किसी प्रकार से उक्त सस्थान के लाइसेंस के लिये सस्तुति की है । वस्तुस्थिति यह है कि गत बजट अधिवेशन के उठने के कुछ ही दिन बाद सी बी आई के कुछ अधिकारी मेरे दिल्ली निवास स्थान पर इस साध मे जाच के लिये आये थे । उनको मैंने स्पष्टत बता दिया था कि उस सस्तुति पत्र पर न तो मेरा हस्ताक्षर है और न इनसे मेरा कोई किसी प्रकार का संबध है । मुझे यह जान कर आश्चर्य एव दुख हुआ है कि श्री डी पी चट्टोपाध्याय राज्य वाणिज्य मंत्री भारत सरकार ने इस प्रसग मे राज्य सभा मे मेरे नाम का उल्लेख किया है जो निराधार और निर्मूल है ।

इस सबध मे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं । श्री चट्टोपाध्याय राज्य सभा के सदस्य हैं, लोक सभा के नहीं हैं । क्या किसी राज्य सभा के सदस्य के लिए यह जानते हुये कि सारे के सारे लोक सभा के सदस्य है और यह भी जानते हुये कि सब इनक्वायरी हो चुकी है इस तरह से लांछन करना उचित है और क्या यह उसके विरूद्ध मान हानी का सवाल नहीं बनता है ?

श्री हुकम चन्द कछवाय (मुरेना) वह सरकारी मंत्री हैं ।

श्री राम स्वरूप (रावर्ट सगज) : अध्यक्ष महोदय, कल राज्य सभा मे हुये तारांकित प्रश्न सख्या 730 के उत्तर मे वाणिज्य मंत्री श्री डी० पी चट्टोपाध्याय ने जिस सबधित फर्म को आयात लाइसेंस देने की सस्तुति करने वाले ससद् सदस्यो की सूची सभा पटल पर रखी थी उसमे मेरा नाम भी लिखा हुआ है । खेद का विषय है कि उक्तसूची मे मेरा नाम उन्होने कैसे शामिल कर लिया जबकि मैंने इस प्रकार के कोई हस्ताक्षर नही किये थ । इस सबध मे सी बी आई अधिकारी भी मुझ से पूछताछ कर गये थे और मैंने स्पष्ट कर दिया था कि उक्त प्रार्थना पत्र पर मेरे हस्ताक्षर नही हैं, न ही मैं उसके सबध मे कुछ जानता हू ।

मुझे आश्चर्य और खेद है कि जब इस सबध मे सी बी आई अब भी जाच पडताल की कार्यवाही कर रहा है, इस बीच वाणिज्य मत्री ने मेरा नाम कैसे जोड़ दिया ।

कृपया इस सम्बन्ध मे मेरे स्पष्टीकरण का देखते हुए उचित निर्णय लें ताकि भविष्य में इस प्रकार से मेरी प्रतिष्ठा के विरुध कोई कार्यवाई न की जा सके ।

श्री नागेन्द्र प्रसाद यादव (सीतामढ़ी): अध्यक्ष महोदय, दिनाक 27-8-74 को कल जब मे ससद मे आया तो ज्ञात हुआ कि राज्य सभा मे वाणिज्य मंत्री भारत सरकार,ने एक फर्म को लाइसेंस देने की बाबत तारांकित प्रश्न संख्या 730 के सदर्भ मे उत्तर दिया है और कहा है कि आवेदन पत्र मे मेरे भी हस्ताक्षर है और वह वेरिफिकेशन के अन्दर है । मुझे इस पर अत्यन्त दुख हुआ है और मैं श्रीमान् से व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहता हू

(1) कथित आवेदन पत्र पर मेरा हस्ताक्षर नहीं है ।

(2) मेरा हस्ताक्षर जाली है ।

(3) मुझे इस आवेदन पत्र से कोई ताल्लुक नही है ।

(4) कुछ माह पूर्व सी बी आई के एक अधिकारी मेरे निवास स्थान पर आए और मुझे उन्होने हस्ताक्षर दिखलाया था । उस समय ही मैंने हस्ताक्षर को इन्कार किया था और कहा था कि मेरा यह हस्ताक्षर जाली बनाया गया है ।

(5) मन्त्री महोदय के बयान से मेरी प्रतिष्ठा पर घोर आघात पहुचा है ।

(6) मेरा आप मे निवेदन है कि इसका निराकरण तथा मुझे सतोष तभी हो सकता है जबइस की पूरी जाच हो और दोषी व्यक्ति को दडित किया जाय ।

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे (खलीलाबाद) : अध्यक्ष महोदय, कल राज्य सभा मे एक अत्यन्त ही खेदजनक वक्तव्य माननीय वाणिज्य मत्री श्री डी०पी० चट्टोपाध्याय द्वारा दिया गया जिस मे न केवल माननीय ससद सदस्यो की प्रतिष्ठा पर आघात पहुचा बल्कि जनतत्र से विश्वास करने वाले देश के उन तमाम नागरिको से हम लोगो का विश्वास उठा लिया गया कि हम लोग जाली और फर्जी हस्ताक्षर करते हैं । जब मैं 27-8-74 को ससद मे आया तो मुझे ज्ञात हुआ कि राज्य सभा मे वाणिज्य मत्री श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय ने कुछ फर्मो को लाइसेंस देने के बारे मे तारांकित प्रश्न सख्या 730 के सदर्भ मे उत्तर दिया है और उस उत्तर में मेरा भी नाम जोड दिया है कि उस आवेदन पत्र पर मेरे भी हस्ताक्षर हैं । अर्थात् कृष्ण चन्द्र पांडे के भी हस्ताक्षर है । उन्होंने अपने उत्तर में कहा कि इस की जांच पड़ताल हो रही है जब कि बजट सत्र के उठने के पहले हम तमाम ससद् सदस्यों के फ्लैट में एक अधिकारी गए थे और हम लोगों को हस्ताक्षर दिखलाया था कि यह आप का हस्ताक्षर है या आप का हस्ताक्षर नही है । 20 ससद् सदस्यो ने लगातार यह कहा कि यह हस्ताक्षर हम लोगो का नही है और हस्ताक्षर फर्जी है, उस के बावजूद भी माननीय मत्री जी ने राज्य सभा मे यह नही कहा कि जो हस्ताक्षर सी बी आई द्वारा मैंने जांच कराए, सी बी आई ने यह कहा कि ये हस्ताक्षर जाली हैं । उन्होंने दोबारा जब उत्तर दिया तब भी यह स्पष्ट नही कहा कि सी बी आई ने हमे बताया है कि हस्ताक्षर जाली है । हम लोगों ने उन को लिखित भी दिया कि जो वक्तव्य आप ने राज्य सभा मे दिया है वह गलत है, आप पुन जा कर वक्तव्य दीजिए ।

श्री मधु लिमये : मेरा प्वाइट आफ आर्डर है । इन्होने जो लिख कर आप को दिया है वही पढें । और बातें इन को नहीं कहनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय यह प्वाइट आफ आर्डर ठीक है । जो आप ने लिख कर दिया वही

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे मुझे इस पर अत्यन्त ही खेद हुआ और मैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहता हू कि कथित आवेदन पत्र पर मेरा हस्ताक्षर कदापि नही है । मेरा हस्ताक्षर जाली है । मुझे इस आवेदन पत्र से कोई और किसी प्रकार का ताल्लुक नहीं है । कुछ माह पूर्व सी बी आई के एक अधिकारी मेरे फ्लैट पर आए थे और मुझे हस्ताक्षर दिखाया था । उस समय ही मैंने हस्ताक्षर को इकार किया था और कहा था कि मेरा हस्ताक्षर जाली बनाया गया है । मत्री महोदय के बयान से मेरी प्रतिष्ठा पर घोर आघात पहुंचा है । इस का

[श्री कृष्ण चन्द्र पांडे]

निराकरण तथा मुझे संतोष तभी होगा जब इस की पूरी जांच हो और दोषी को दंडित किया जाय ।

SHRI MOHAMMAD TAHIR (Purnea): I beg to submit that I was much shocked on 27th August, 1974 to hear that my name has been dragged unnecessarily while replying the Starred Question No. 730 dated 27th August, 1974 of the Rajya Sabha and I would like to submit the following points by way of personal explanation:

(a) That I have not signed the alleged application for licence.

(b) That my signature is forged one.

(c) That I have no concern with the application for licence.

(d) That I emphatically denied before the C.B.I. officer who came to me some months back to my flat for enquiry and verification of my signature and I asserted that my signature is forged one.

(e) That I have been defamed and injured by the Hon'ble Minister for Commerce as he unnecessarily dragged my name in the Rajya Sabha though as a matter of fact I had already stated that my signature is forged one and by giving out my name in the other House I have been defamed and this House has also been defamed.

(f) That you are my guardian and custodian of the honour and prestige and of this House also and as a guardian I seek your protection.

I further submit that full investigation be made into the matter to bring the culprit to the book and I further add that the licence so granted be cancelled forthwith.

SHRI HARI KISHORE SINGH (Pupri): I beg to make a statement concerning Starred question No. 730 in the Rajya Sabha on 27th August, 1974 in which Shri D. P. Chattopadhyaya, Minister of Commerce mentioned my name to be one of those who have allegedly signed a memorandum for grant of licence to some firms.

I most emphatically deny this and had made this clear to the CBI officer who had come to enquire in this matter. It is a very serious matter and has larger implications. Not only the dignity, integrity and honour of some hon'ble Members at a stake but if things like this get currency the whole institution of Parliamentary democracy will be undermined. It is, therefore, necessary that the truth should be found out and those responsible for this most reprehensible act be punished, whether they are members of Parliament, Ministers or officers or businessmen and their agents. Unless this is done and the entire matter is made public the doubts cast on the fair names of the Members shall not be cleared Therefore, Sir, I most emphatically demand a Parliamentary probe in this whole issue

SHRIMATI SAVITRI SHYAM (Anola): I beg to say that I am pained to note that in reply to Starred Question No 730 dated 27th August, 1974 in the Rajya Sabha, the Commerce Minister Shri D. P. Chattopadhyaya mentioned my name, to be one of the signatories to an alleged memorandum on the basis of which some licence had been issued.

Sir, in this connection I may tell that perhaps C.B.I. Officer or someone had visited my house some months back and asked me showing a memorandum that whether that signature was mine. I denied it emphatically and said that it is forged one.

Sir, it is very unfortunate that in spite of this clear denial, my name was mentioned.

Sir, I want to make it crystal clear that I have got no concern with any of such memorandum and my alleged signature is forged. My name has unnecessarily been dragged.

Sir, you are the custodian of the prestige of the Members of this House and hence I will pray that my name

should be dropped and after the enquiry the culprit who forged the signature should be taken to task.

कुमारी कमला कुमारी (पालामऊ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल दिनांक 27—8—74 को मुझे ज्ञात हुआ कि वाणिज्य मंत्री ने राज्य सभा में कुछ फर्मों को लाइसेंस देने की बाबत तारांकित प्रश्न के उत्तर में कहा है कि आवेदन पत्र में मेरा कथित हस्ताक्षर है और इसकी जांच पड़ताल हो रही है। मुझे इस पर अत्यन्त दुख है और व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहती हूं। (1) कथित आवेदन पत्र पर मेरा हस्ताक्षर कदापि नहीं है। (2) मेरा हस्ताक्षर जाली है। (3) मुझे आवेदन पत्र से कोई सम्बन्ध नहीं है। (4) कुछ माह पूर्व सी० बी० आई० के दो अधिकारी रात लगभग 10 00 बजे मेरे घर पर आये और उन्होंने मेरे हस्ताक्षर दिखाए। मैंने उस हस्ताक्षर के सम्बन्ध में कहा कि यह मेरे हस्ताक्षर नहीं है। तथा साफ शब्दों में मैंने इन्कार किया कि वे हस्ताक्षर जाली किए गए हैं।

मंत्री के बयान से मेरी प्रतिष्ठा पर घोर आघात पहुंचाया गया है और हमारे सम्मान का कोई भी ख्याल नहीं किया गया है। इसलिए आप से निवेदन है कि अगर इस तरह से किसी भी पार्लियामेंट मेम्बर के सम्मान को घोर आघात सदन में पहुंचाया जाता है तो यह बहुत ही अपमानजनक बात होती है। साथ ही इसका निराकरण तभी ही हो सकता है जब कि इस की पूरी जांच-पड़ताल हो और साथ ही यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है, किसी संसद सदस्य पर किसी तरह का लांछन लगाता है तो उस को घोर दण्ड दिया जाए।

श्री शंकर जाडे : (मदला) अध्यक्ष महोदय, कल दिनांक 27—8—74 को मुझे ज्ञात हुआ है कि वाणिज्य मंत्री ने राज्य सभा में कुछ फर्मों को लाइसेंस देने की बाबत तारांकित प्रश्न के उत्तर में कहा है कि आवेदन पत्र में मेरा कथित हस्ताक्षर है और इस की जांच-पड़ताल हो रही है। मुझे इस पर अत्यन्त दुख है और व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहता हूं (1) कथित आवेदन पत्र पर मेरा हस्ताक्षर कदापि नहीं है। (2) मेरा हस्ताक्षर जाली है। (3) मुझे आवेदन पत्र से कोई सम्बन्ध नहीं है। (4) कुछ माह पूर्व सी० बी० आई० के दो अधिकारी रात लगभग 10 बजे आये थे और मुझे हस्ताक्षर दिखाये तो उस समय भी मैंने हस्ताक्षर से इंकार किया था और कहा था कि मेरा हस्ताक्षर जाली बनाया गया है। (5) मंत्री के बयान से मेरी प्रतिष्ठा पर घोर आघात पहुंचा है। (6) इसका निराकरण तथा सतोष तभी होगा जब इस की जांच हो तथा दोषी को दण्डित किया जाए।

SHRI INDER J. MALHOTRA (Jammu): In all seriousness, I would like to submit most humbly at the very outset that I have got nothing to do with the document which is under discussion. In fact, if I can recall correctly, about four months back, two officials of the CBI came to my residence, they showed me a document in which along with the names of other Members, my name was also written. Those officers wanted to know whether those were my signatures. I immediately showed them the other papers where I had put my signatures only a few minutes before and placed those papers before the officers. The style in which my name was written on that document was entirely different from my usual way or normal way of signing papers.

I am really pained at one or two points, particularly at the way this matter has been answered and this matter has been brought up in the other House. As Shri Vajpayee and Shri Shyamnandan Mishra wanted to know from Government, who asked the CBI to go to the Members to verify or ascertain whether those Members had signed that document or not? If the Ministry of Commerce or the Minister of Commerce had asked the CBI officers to go and verify from the Members, then it was the duty of the hon. Minister to have placed the entire

[Shri Inder J. Malhotra]

facts before this House or to the other House.

It is really very unfortunate, and I am really pained to make these submissions.

In spite of the fact that the Government knew that the CBI officers had made enquiries and had made verification, what was the need for hiding those facts from the other House when the answer was given?

Therefore, I would very humbly submit to you and through you to this House that we must take a very serious note of this. As has been demanded by other hon. members, I would also like to place my demand before the House that a Special Parliamentary Committee be constituted to go into the entire episode and then come out with a report before this House so that the names of those members whose signatures have been forged and who are being maligned without any reason or for any mistake or act done by them, are absolutely cleared and placed before this House and the country.

SHRI S C BESRA (Dumka): Mr. Speaker, Sir, I beg to say that I am pained to note that in reply to Starred Question No. 730 dated 27th August, 1974 in the Rajya Sabha, the Commerce Minister, Shri D. P. Chattopadhyaya, mentioned my name to be one of the signatories on an alleged memorandum on the basis of which some licence had been issued

In this connection, I may say that one CBI officer had visited my house some months back and asked me showing a memorandum whether that signature was mine I denied it emphatically and said that this was a forged one.

It is very unfortunate that in spite of this clear knowledge, the hon. Commerce Minister had mentioned my name.

I want to make it crystal clear that I have got no concern with any of such memorandum and my alleged signature is forged. My name has unnecessarily been dragged.

Sir, you are the custodian of the prestige of the member of this House and hence I pray that my name should be dropped for ever and after due inquiry the culprit who forged the signature should be taken to task.

श्री चन्द्र शेखानी (हाथरस) : माननीय अध्यक्ष महोदय, में अभी उपस्थित नही था, इस के लिए क्षमा चाहता हूं। मेरे पेट में दर्द हो रहा था, इस लिए नही आ पाया था।

मै आप की सेवा में निवेदन करना चाहता हूं—कल दिनाक 27—8—74 को मुझे ज्ञात हुआ कि वाणिज्य मंत्री ने राज्य सभा में कुछ फर्मों को लाइसेंस देने के बाबत तारांकित प्रश्न के उत्तर में कहा है कि आवेदन पत्र में मेरा कथित हस्ताक्षर है और इस की जांच पडताल हो रही है। मुझे इस पर अत्यन्त दुख है और व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। कथित आवेदन पत्र पर मेरा हस्ताक्षर कदापि नही है। मेरा हस्ताक्षर जाली है। मुझे आवेदन पत्र से कोई सम्बन्ध नही है। कुछ माह पूर्व सी० बी० आई० के दो अधिकारी रात लगभग 10 बजे आये थे और मुझे हस्ताक्षर दिखाए तो उस समय भी मैंने हस्ताक्षर से इन्कार किया था और कहा था कि मेरा हस्ताक्षर जाली बनाया गया है। मंत्री के बयान से मेरी प्रतिसेष्ठा पर घोर आघात पहुचा है। इस का निराकरण तथ संतोष तभी होगा जब इस की जाच हो तथा दोषी को दण्डित किया जाए।

श्री चिरंजीव झा (सहरसा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, तारांकित प्रश्न सं० 730 दिनांक 27—8—74 के उत्तर के क्रम में वाणिज्य मंत्री श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय ने कल अन्य ससद सदस्यों के साथ मेरे नाम का भी जो उल्लेख राज्य सभा में किया, उस प्रसंग मे मेरा निवेदन है कि किसी फर्म के लाइसेंस के लिए उस के आवेदन पत्र पर न तो मैंने हस्ताक्षर किया है और न उस से मेरा किसी तरह का ताल्लुक है।

14.00 hrs.

कुछ माह पूर्व जब मेरे निवास स्थान पर सी० बी० आई० के दो अफसर इस प्रसंग में जांच पडताल करने आए तो मैं आश्चर्यचकित हो गया। उनसे मैंने स्पष्टत: कहा कि इसपर मेरे हस्ताक्षर नहीं है। और जिस तरह से मैं साधारणतया अपना हस्पाक्षर करता हूं उससे एकदम भिन्न वह हस्ताक्षर भी थे। मैंने अपने अलग हस्ताक्षर भी वहाँ किए और उन लोगों ने कहा इससे भिन्न वह हस्ताक्षर हैं। मुझे उस कम्पनी से जिसके नाम से लाइसेंन्स के लिए दरख्वास्त थी किसी तरह का कोई सम्पर्क नहीं है। ऐसी स्थिति में राज्य सभा में मेरे नाम की चर्चा कर मैं समझता हूं मेरे प्रति अन्याय किया गया है। अत: मेरा आग्रह है कि मेरे इस व्यक्तिगत स्पष्टीकरण को स्वीकार कर मेरे प्रति न्याय करने की कृपा की जाए ताकि मेरी प्रतिष्ठा की रक्षा हो सके।

अध्यक्ष महोदय, साथ ही मेरा निवेदन यह भी ह कि हमें तभी संतोष होगा जब इस बिषय की पूरी छान-बीन की जाए और पूरी छान-बीन करके जो दरअसल दोषी है उसे दण्डित किया जाए। तभी हमको संतोष होगा और खुशी होगी और इस सदन की गरिमा तथा मर्यादा की भी रक्षा हो सकेगी जिसके आप संरक्षक है। तो इसकी पूरी तरह से छान बीन की जानी चाहिए, यही मेरा आपसे विनीत आग्रह है।

MR. SPEAKER: I have heard those Members who gave the motions; I have heard those Members who are involved. Now, I will allow the Minister and then I will allow a debate, not today, but I will consider under what rule this should come.

I have allowed those Members who gave the motions. Now, I will allow the Minister. I will let you know later on, what procedure I will follow.

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय. मैं केवल एक मिनट चाहता हूं। आप मुझेसुन लें।

MR. SPEAKER: बिल्कुल नहीं सुनुगां। आपको सुनूंगा तो दूसरो को सुनना पड़ेगा।

I am not allowing you. Kindly sit down.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI A. C. GEORGE): Sir, at the very outset, I would like to humbly submit on my behalf and on behalf of my senior colleague, Prof. Chattopadhyaya

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: How can you do that?

MR. SPEAKER: You can speak on behalf of the Government.

SHRI A. C. GEORGE: At the outset, may I humbly submit on behalf of the Government that we feel extremely pained to have hurt the feelings of this august House, especially the members whose names were mentionin reply to Question 730 in the Rajya Sabha yesterday. If you bear with me for a moment, I am sure you will appreciate that this was unintentional. As I said, the question asked was: "what were the names of the MPs who had allegedly signed the representation referred to in the Blitz dated 30th March, 1974 and the date on which it was received in the ministry". In reply, we reiterated that when the news item published in the **Blitz** came to Government's notice, a secret verification through the CBI was initiated. Once a question is admitted in a clear and unambiguous manner and the word "alleged" is there, we take it that it is a direction from the Chair for the minister to answer unambiguously. We would otherwise have been running the risk

[Shri A. C. George]

of the opposition accusing us that we were trying to protect these members. They will say, "We are only asking for names of MPs who have allegedly put their signatures". That is why in deference to the House and considering it as a direction from the Chair, these names were given out and we never meant it as an insult to the members.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: We could have taken the plea of public interest.

SHRI A. C. GEORGE: If you go through the replies further, you will see that my senior colleague has made it amply clear more than three times, that after this complaint was brought to our notice, our normal presumption would be that the signatures on this representation were not genuine, unless anything to the contrary came to light. It was made clear in the other House itself that as soon as the news item came in the press and there was an air of suspicion, from that moment we presumed that the signatures were not genuine, because we consider the members' honour as important as anyone else would consider it. As soon as this news item was brought to our notice, immediately the matter was referred to the CBI for verification. It was a matter for quiet and discreet verification because the names involved were those of 21 hon. members. Sir, in matters of signature you and I are not experts Naturally expertise was needed and here was a situation for making some quiet and discreet verification.

SHRI VASANT SATHE (Akola): What was the report of the CBI?

SHRI A. C. GEORGE: The most important fact relevant to the situation is, till the hon. Members declared in their own handwriting, we did not have any interim or final report from the CBI. Only when this question came up we asked for the names and only when 18 members yesterday and two members today, if I remember correct . . .

SHRI C. M. STEPHEN: Are we to take it that you did not have the representation before you when you reported the matter to the CBI?

SHRI A. C. GEORGE: You must appreciate that this representation was submitted on the 23rd November 1972. In the Ministry we get so many representations.

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे (खलीलाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मेरा पोइंट आफ आर्डर है। इन्होंने सी० बी० आई० को इनक्वायरी करने के लिए इसे सौंप दिया । लेकिन जब उत्तर इन्होंने कल दिया राज्य सभा में उस वक्त इन्होंने नहीं पूछा कि सी० बी० आई० वालों ने क्या हम से पूछा कर जांच की है। हम लोगों ने जब कहा कि हमारे हस्ताक्षर फर्जी हैं इस के बाद भी इन्होंने उत्तर दिया है। प्रश्न यह है।

MR. SPEAKER: This is not a point of order.

SHRI A. C. GEORGE: I am only pointing out two facts—one was strictly abiding by the spirit and letter of the question asked and, secondly, we were going on the basis of the information available with us. All the same, as I pointed out in the beginning, since this has hurt the feelings of the House, on behalf of the Government I feel sorry and I express my regret.

श्री मधु लिमये : सौरी क्यों, जब तक इन्वेस्टीगेशन पूरा न हो।

MR SPEAKER: We will continue this debate on some other day. In the meanwhile, I will try to find out what should be the procedure. Personally, I feel it is a very important subject over which we must apply our mind and settle down certain procedures. Now the rule is that when one member makes an allegation against another member, he should give notice to the other member. If some people go to the extent of getting even forged or fictitious signatures, we have to go into the matter thoroughly. We should not only consider the present case in its proper perspective and consider

what action should be taken about it but also see, if such cases occur and the Minister is in possession of certain facts, whether it is not necessary that he should either ask for information from the member or at least convey to the Speaker that some members are involved like this and ask for his directions. These are the various issues over which we can have some views I cannot give any off hand ruling at present We will take up this subject again some other day. We will consider by that time what procedure should be adopted.

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam): Even regarding the procedure we have not yet heard the Minister concerned, namely, Prof Chattopadhyaya. Only the Deputy Minister has replied to the points.

SHRI A C GEORGE: Even yesterday night it was made plain that Prof. Chattopadhyaya has to go to Iran on a mission of national importance.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: The hon Minister has not told us two things which would be very material for your consideration The point that we have submitted is that certain information, the denial of the Members, was withheld from the House and the confirmation of the information was also withheld from the House.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, कल राज्य सभा में सवेरे मामला उठा, और मेम्बरों के नाम मारे पढ कर बताए गए। और फिर मंत्री महोदय को कहा गया कि शाम को बयान दें। लेकिन शाम का जो बयान है उस में भी सी० बी० आई० ने इन मेम्बरों से सम्पर्क किया, इन मेम्बरों ने मना किया कि हमारे दस्तखत नही है, जाली दस्तखत है। यह बात हाउस में नही बतायी गई। इसका कोई जवाब है इन के पास ?

श्री मधु लिमये : इस में पहले जो मंत्री महोदय का शाम का बयान है उसमें से दो वाक्य आपके सामने रखना चाहता हूं। इन्होंने कहा है कि :

"Madam Vice-Chairman, during Question Hour today I had stated in reply to suplementaries arising out of Starred Question No. 730 about a representation received by the Ministry of Commerce on 23rd November, 1972 allegedly bearing the signature of 21 hon. Members of Parliament that the matter was still under verification and that our normal presumption would be that the signatures on this representation were not genuine unless anything to the contrary came to light"

यह ऐबसर्ड प्रीपोजीशन है। अगर मेरे सिगनेचर से कोई पत्र जाता है जब तक मैं डिनाई नही करता हूं तो यह प्रीपोस्टरस प्रीजम्पशन कैसे ? इसका मतलब तो यह हुआ कि उनको मालूम हो गया था कि सी०बी०आई० के सामने उन्होंने डिनाई किया था। अगर मालूम हो गया था तो यह जानकारी राज्य सभा के सामने लानी चाहिए थी। आगे कहते है :

"I would like to reiterate that till the process of verification and confirmation is completed, I would maintain my presumption that the alleged signatures of the other hon. Members are also not genuine."

जब तक वह डिनाई नही करते हैं तब तक प्रीजम्पशन कैसा ? डिनाई किया तो प्रीजम्पशन ठीक है। जिन्होंने डिनाई नही किया उन के बारे मे मंत्री महोदय ने कहा है कि हमारा प्रीजम्पशन है। इसका साफ जवाब दिलाइये।

SHRI A. C GEORGE: It is very clear that after this news item appeared in the Blitz Weekly of 30th March, 1974 and, after it was referred to the CBI in the case of the hon. Members of Parliament, we have to presume that this is the position. That is why he has said that.

श्री शंकर दयाल सिंह (चतरा) : अध्यक्ष महोदय, इस मामले को दूसरे दिन के लिये यहीं टाला जाय बल्कि आज ही ज्यादा देर तक बैठ कर इस मामले को समाप्त करें इसकी गम्भीरता को देखते हुए।

MR. SPEAKER: Papers to be laid.

14.19 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Review and Anual Report of Hindustan Cables Ltd. for 1972-73 and Annual Report of Controller General of Patents, Designs and Trade Marks for 1973-74.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI ZIAUR RAHMAN ANSARI): Sir, on behalf of Shri C. Subramaniam, I beg to lay on the Table—

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:—

(i) Review by the Government on the working of the Hindustan Cables Limited, for the year 1972-73.

(ii) Annual Report of the Hindustan Cables Limited, for the year 1972-73 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[*Placed in Library. See No. LT-8313/74*].

(2) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Controller General of Patents, Designs and Trade Marks for the year 1973-74, under section 155 of the Patents Act, 1970. [*Placed in Library. See No. LT-8314/74*].

14.19½ hrs.

QUESTION OF PRIVILEGE—contd.

CERTAIN STATEMENTS MADE BY THE MINISTER OF COMMERCE IN RAJYA SABHA RE. ALLEGED SIGNATURES OF SOME M.PS. ON A REPRESENTATION FOR ISSUE OF LICENCES.

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI L. N. MISHRA): Sir, I want to give a personal explanation. (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : इन का कहना है कि मेरा नाम इन्होंने बार-बार लिया है इसलिये मैं पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं।

SHRI MADHU LIMAYE (Banka): Have you read and approved it, Sir?

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिख कर भेज दीजिये क्योंकि प्रोसीजर यह है कि

I must get a copy of that.

SHRI L. N. MISHRA: Because my name has been brought in the discussion....

MR. SPEAKER: On the spot also you can give, because the matter was raised today.

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (ग्वालियर): पहले आप ने कहा कि लिख कर दे दीजिये और अभी आप कहते हैं कि एक्सप्लानेशन दे दीजिये। इतनी जल्दी तो मत बदलिये।

MR. SPEAKER: Because allegations have been made, he has the right to reply. He can reply on the spot. But if he wants to be more careful, then he can give in writing. It is upto him.

SHRI L. N. MISHRA: Mr. Speaker, Sir, since my name has been mentioned, I would like to make a brief statement by way of personal explanation. I recollect having received a letter purporting to bear the signatures of a number of MPs when I was in charge of the former Ministry of Foreign Trade. As far as I remember, I passed on the letter to the officer concerned in the normal course of business. No order was passed by me, nor any licence was issued during the period